

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1813
जिसका उत्तर मंगलवार 06 मार्च, 2018 को दिया जाना है

विद्युत वाहन

1813. श्री विद्युत वरण महतो:

श्री टी राधाकृष्णन:

श्री ए अनवर राजा:

श्री नारणभाई काछडिया:

श्री गजाजन कीर्तिकर:

श्री सुधीर गुप्ता:

कुँवर हरिवंश सिंह:

श्री एस आर विजय कुमार:

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सार्वजनिक यातायात हेतु भारतीय सड़कों पर चलने वाले सभी वाहनों को 2030 तक विद्युत वाहनों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) वर्तमान में देश में कितनी विद्युत बसों का निर्माण किया गया है;
- (घ) हाइब्रिड/विद्युत बसों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या छूट दी गई है; और
- (ङ) क्या विद्युत बसों की कीमत अन्य वाहनों की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और देश में विद्युत बसों की कीमत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): सार्वजनिक यातायात हेतु भारतीय सड़कों पर चलने वाले सभी वाहनों को 2030 तक विद्युत वाहनों में परिवर्तित करने के लिए इस समय भारी उद्योग विभाग के विचारार्थ कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ड): चूंकि ऑटोमोबाइल क्षेत्र उदारीकृत क्षेत्र है जिसमें 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, भारी उद्योग विभाग वाहनों के विनिर्माण से संबंधित आकड़ें नहीं रखता है।

विभाग की फेम इंडिया स्कीम के अंतर्गत, हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक बसों के विनिर्माण हेतु कोई छूट नहीं दी गई है।

बेटरी की उच्च लागत के कारण पारंपरिक आसीई बस की तुलना में इलेक्ट्रिक बस की लागत काफी अधिक है। तथापि, इसे किफायती बनाने के लिए योजना की अधिसूचना के अनुबंध-13 के अंतर्गत तालिका संख्या 5 और 6 के अनुसार तथा राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ.3012(ई) दिनांक 12.09.2017 के अनुसार हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक बसों के लिए मांग प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जो भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध हैं।
